कामये दुरवतप्राणाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष.65 अंक.01 मुंबई दिसम्बर, 2020

खादी इण्डिया ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की

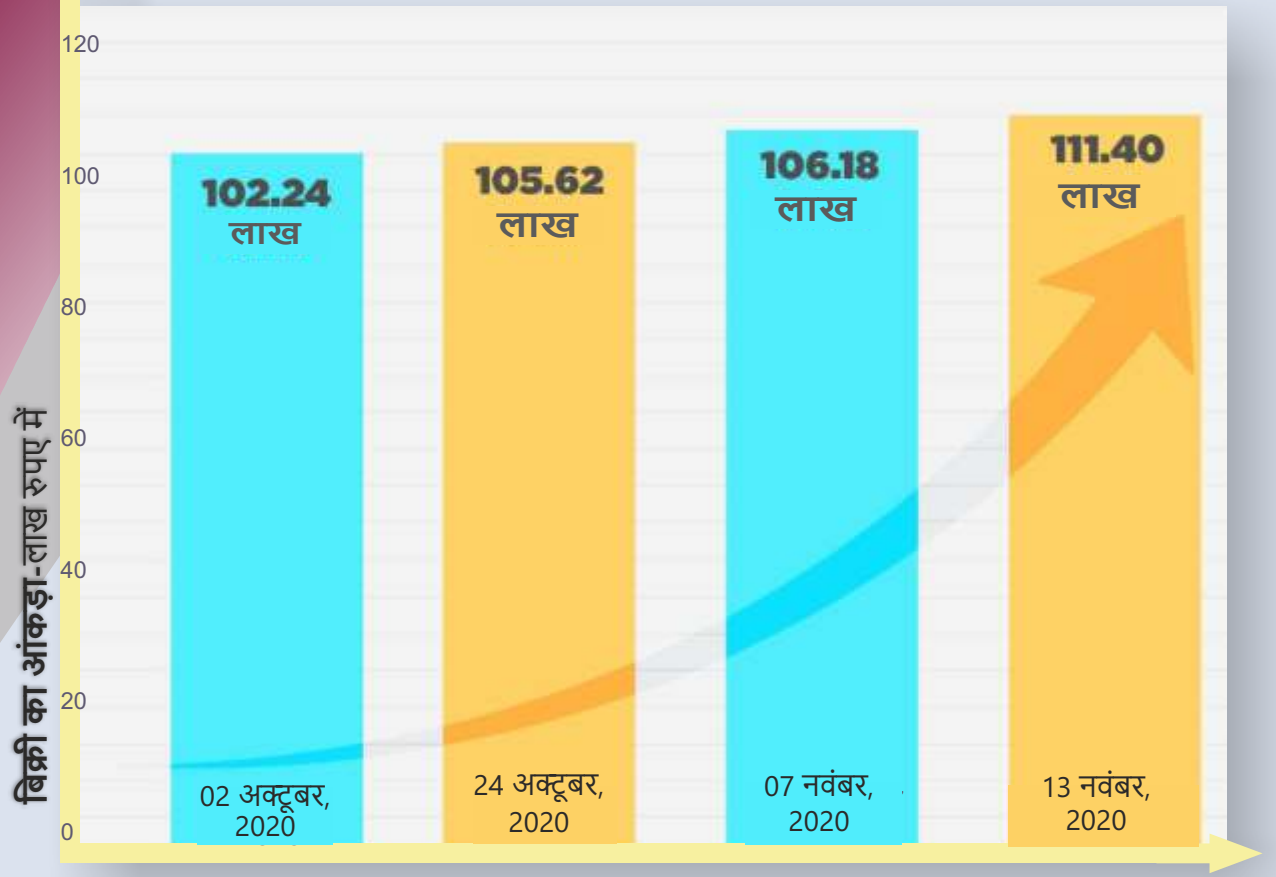

कनॉट प्लेस स्थित आउटलेट में 40 दिनों में चौथी बार, एक दिन में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

वर्ष:65 अंक-1 मुम्बई दिसम्बर 2020

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार
शिव दयाल कुशवाहा

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार 03-23

खादी ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की.....

एमएसएमई मंत्री द्वारा बांस प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन.....

केवीआईसी का ई-पोर्टल कुम्हारों के लिए समय से पहले दिवाली लाया .....

कारगिल-लेह में रोजगार का सृजन कर चेहरों पर मुस्कान ला रही है खादी .....

अरुणाचल प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चे खादी के मास्क पहनेंगे.....

वाराणसी में आयोग द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन.....

केवीआईसी की वर्कशेड योजना के तहत पक्के घर मिलने से पूर्वोत्तर के खादी कारीगरों के चेहरों पर मुस्कान.....

'भारत में मसाला क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर' प्रदान करने के लिए उद्यमियों हेतु वेबिनार में आयोग के अध्यक्ष ने संबोधित किया .....

केवीआईसी के हनी मिशन से प्रवासी श्रमिकों को पहली आय अर्जित.....

आयोग ने संविधान दिवस मनाया .....

चेतावनी सूचना .....

महाराष्ट्र में पीएमईजीपी इकाईयों एवं बांस स्फूर्ति क्लस्टर का निरीक्षण .....

मीडिया कवरेज..... 24-26

खादी ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की

कनॉट प्लेस स्थित आउटलेट में 40 दिनों में चौथी बार, एक दिन में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री

आर्थिक तंगी और कोरोना महामारी के भय को पीछे छोड़ते हुए, इस त्योहारी सीजन ने खादी कारीगरों को खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री के साथ शानदार लाभांश दिया है। इस वर्ष दो अक्टूबर के बाद से केवल 40 दिनों में, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के प्रमुख आउटलेट पर खादी की एक-दिन की बिक्री का आंकड़ा चौथी बार एक करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया है।

13 नवंबर को, इस आउटलेट की कुल बिक्री 1.11 करोड़ रुपए रही, जो इस साल किसी एक दिन में सबसे बड़ी बिक्री का आंकड़ा है। जब से लॉकडाउन के बाद व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हुईं, खादी की बिक्री का आंकड़ा इस साल गांधी जयंती (दो अक्टूबर) को 1.02 करोड़ रुपए और 24 अक्टूबर को 1.05 करोड़ रुपए और सात नवंबर को 1.06 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

इससे पहले 2018 में, एक दिन की बिक्री ने चार मौकों पर एक करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। 13 अक्टूबर, 2018 को 1.25 करोड़ रुपए की बिक्री एक दिन की बिक्री का सबसे बड़ा आंकड़ा थी। खादी की एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री 1.27 करोड़ रुपए दर्ज की गयी है जो 02 अक्टूबर, 2019 के दिन हासिल हुई थी। गौरतलब है कि 2016 से पहले खादी की एक दिन की बिक्री कभी भी एक करोड़ रुपए के पार नहीं गई थी। 22 अक्टूबर, 2016 को कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के आउटलेट पर एक दिन की बिक्री का आंकड़ा पहली बार एक करोड़ रुपए के पार गया था, यह 116.13 लाख रुपए था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री की "स्वदेशी", विशेषकर खादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार की गई अपील को बड़े पैमाने पर हुई बिक्री के आंकड़ों का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों की रीढ़ बनाने वाले कारीगरों का

कनॉट प्लेस, दिल्ली स्थित खादी इंडिया आउटलेट में बिक्री का रिकार्ड आंकड़ा

समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में खादी प्रेमियों को आते देखकर खुशी होती है।

महामारी के बावजूद, खादी कारीगरों ने उत्पादन गतिविधियों को पूरे जोश के साथ जारी रखा और साथी देशवासियों ने भी उसी उत्साह के साथ उनका समर्थन किया।" केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद, केवीआईसी ने खादी के विकास की गति को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है।

इस वर्ष खादी उत्पादों की जबरदस्त बिक्री काफी महत्व रखती है। जहां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी गतिविधियां रुक गयी थीं, केवीआईसी ने देश भर में अपनी विविध गतिविधियां जारी रखीं जिसमें फेस मास्क और हैंड वॉश एवं हैंड सेनिटाइज़र जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों के अलावा कपड़े और ग्राम्य उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला का उत्पादन शामिल है।

लॉकडाउन का खादी कारीगरों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" की अपील ने स्थानीय विनिर्माण विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में एक नयी जान डाल दी।

खादी की एक दिन की बिक्री का आंकड़ा:

- 04 अक्टूबर, 2014 - 66.81 लाख रु.
- 02 अक्टूबर 2015 - 91.42 लाख रु.
- 22 अक्टूबर, 2016 - 116.13 लाख रु.
- 17 अक्टूबर, 2017 - 117.08 लाख रु.
- 02 अक्टूबर, 2018 - 105.94 लाख रु.
- 13 अक्टूबर, 2018 - 125.25 लाख रु.
- 17 अक्टूबर, 2018 - 102.72 लाख रु.
- 20 अक्टूबर, 2018 - 102.14 लाख रु.
- 02 अक्टूबर, 2019 - 127.57 लाख रु.
- 02 अक्टूबर, 2020 - 102.24 लाख रु.
- 24 अक्टूबर, 2020 - 105.62 लाख रु.
- 07 नवंबर, 2020 - 106.18 लाख रु.
- 13 नवंबर, 2020 - 111.40 लाख रु.

एमएसएमई मंत्री द्वारा
बांस संसाधनों का उपयोग बढ़ाने
और ढुलाई लागत में कमी लाने
की आवश्यकता पर जोर

एमएसएमई मंत्री द्वारा
बांस प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश के बाँस संसाधनों का व्यापक रूप में दोहन करने पर ज़ोर दिया है। वर्चुअल माध्यम से बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए 05 नवम्बर,2020 को आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाँस एक ऐसा संसाधन है जिसका विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह भवनों, घरों की अंदरूनी साज-सज्जा, हस्तशिल्प, अगरबत्ती बनाने, वस्त्र उत्पादन, जैव ईंधन इत्यादि क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाता है।

श्री गडकरी ने इस अवसर पर सभी संबन्धित पक्षों से कहा कि बाँस और इससे बने सामानों की कीमतों में कमी लाने के लिए पारंपरिक मालवाहन के बजाए पानी के रास्ते या रेलमार्गों से इसकी ढुलाई के लिए सस्ते विकल्पों का पता लगाएँ। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी में 3 मीटर खुदाई कर जल्द मार्ग से माल वाहन को संभव बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल मार्ग से बांस और बांस से बने उत्पादों का परिवहन सुगम और सस्ता होगा, जिसका पूर्वोत्तर भारत में बहुतायत में उत्पादन संभव है।

श्री गडकरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से एक व्यापक बांस नीति तैयार करने के लिए भी कहा क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में बांस का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात का ज़िक्र किया कि कैसे उन्होंने बांस काटने की अनुमति की आवश्यकता को ख़त्म करने के मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया था,जिन्होंने पुनः उत्पादित होने के स्वभाव के चलते बांस को वन अधिकारियों से इसे घास की श्रेणी में डालने का निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए लगभग 40 टन प्रति एकड़ के बजाए बांस की ऐसी क़िस्मों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है जो 200 टन प्रति एकड़ की दर से अच्छी उपज देने में सक्षम है। बाँस की अधिक उत्पादन वाली किस्मों के व्यापक उपयोग से विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

श्री गडकरी ने सलाह दी कि बांस की छड़ियों को बांस की गांठों तक कम किया जा सकता है, ताकि नमी दूर हो जाए, जिससे

परिवहन आसान हो जाता है और इसके कैलोरी मान में भी वृद्धि होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस संदर्भ में आईआईटी को एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए कहा जा सकता है।

उन्होंने बांस उत्पादन, प्रसंस्करण और इससे जुड़े व्यवसाय को और अधिक प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया और कहा कि इससे बांस उद्योग को एक टिकाऊ उद्योग के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर), में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत कोविड महामारी के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के प्रयास में लगा है और इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र बांस के विशाल संसाधनों की मदद से एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांस को समग्र भारत में उपयोगी और अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की नई विकास गाथा लिखने के लिए पूर्वोत्तर भारत एक इंजन होगा तो बांस उसका ईंधन है।

डा.जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद बांस संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल और समग्र भारत में इससे जुड़ी तकनीकी जानकारी के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के साथ-साथ बांस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में तीन बांस क्लस्टर विकसित करने का मंत्रालय ने पहले से ही निर्णय लिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों में बांस के संभावित उत्पादन की संभावनाओं का पता लगा रहा है। उन्होंने कहा, पिछले चार वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने बांस के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें असम के दीमा हसाओ में एक बांस औद्योगिक पार्क भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र बांस आच्छादित है। हालांकि, भारतीय वन अधिनियम1927 के तहत बांस की आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के बांस की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए मोदी सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण इसी तथ्य से मिलता है कि उसने बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर लाने हेतु एक सदी पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया है।

डा. जितेंद्र सिंह ने कहा, एक अन्य प्रमुख सुधार के तहत बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क में 25 प्रतिशतकी वृद्धि की गई। इस फैसले के चलते भारत में अगरबत्ती की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई अगरबत्ती स्टिक निर्माण इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा किअगरबत्ती उद्योग की भारत में बाजार हिस्सेदारी 5 से 6 हजार करोड़ रुपये की है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा चीन और कोरिया जैसे देशों से आयात किया जाता रहा।

डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बांस का ऊर्जा के एक स्वच्छ स्रोत के रूप में इस्तेमाल के लिए व्यापक संभावना है और यह सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी स्थान ले सकता है। यह भारत में पर्यावरण और जलवायु को बेहतर करने की भारत की प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाता है।

इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह ने भी संबोधित किया।

केवीआईसी का ई-पोर्टल कुम्हारों के लिए समय से पहले दिवाली लाया

इस बार दिवाली में केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री से सशक्त कुम्हारों के लिए खुशियां आई हैं। राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिलों के सुदूर हिस्सों में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीये खादी इंडिया के ई-पोर्टल की बदौलत देश के हर कोने तक पहुंच रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने इस वर्ष पहली बार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण– वोकल फॉर लोकल को सार्थक बनाने के लिए ऑनलाइन और स्टोर के माध्यम से दीया बेचने का फैसला किया। केवीआईसी ने 8 अक्टूबर को दीये की ऑनलाइन बिक्री शुरू की और एक महीने से भी कम समय में लगभग 10,000 दीये पहले ही ऑनलाइन बिक चुके हैं। केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री के शुरू होने के बाद पहले दिन से ही मिट्टी के दीयों की भारी मांग रही और 10 दिनों से भी कम समय में डिजाइनर दीयों को पूरी तरह से बेच दिया गया था।

इसके बाद, केवीआईसी ने डिजाइनर दीयों के नए सेट लॉन्च किए, जो भारी मांग में भी हैं। दीवाली के निकट आने के साथ ही दीयों की बिक्री भी बढ़ रही है।

केवीआईसी ने 8 प्रकार के डिजाइनर दीये लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 84 रुपये से लेकर 12 के सेट के लिए 108 रुपये है। केवीआईसी इन दीयों पर 10 प्रतिशत की छूट भी दे रहा है। केवीआईसी से जुड़े कुम्हारों ने खुशी व्यक्त की है कि वे हर दीये की बिक्री पर 2 रुपये से 3 रुपये कमा रहे हैं। खादी के डिजाइनर दीये वेबसाइट www.khadiindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

केवीआईसी दिल्ली और अन्य शहरों में अपने आउटलेट के माध्यम से दीया और अन्य मिट्टी की वस्तुओं जैसे लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और अन्य सजावट के सामान भी बेच रहा है। ये मूर्तियां वाराणसी, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में कुम्हारों द्वारा बनाई जा रही हैं और कुम्हारों के लिए अच्छी आय का जरिया बन रही हैं। दूसरी ओर, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जैसलमेर और रावतसर में पोखरण में केवीआईसी इकाइयों से खरीदे जा रहे हैं। विभिन्न खादी आउटलेट्स के माध्यम से 10,000 से

(शेष पृष्ठ 11 पर...)

कारगिल-लेह में रोजगार का सृजन कर चेहरों पर मुस्कान ला रही है खादी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा सृजित स्व-रोजगार के परिणामस्वरूप कारगिल और लेह के शांत हिमालयी क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां फलफूल रही हैं।

2017-18 से केवीआईसी ने कारगिल और लेह में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत लगभग 1000 विभिन्न छोटी और मध्यम विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। इनसे केवल साढ़े तीन साल की अवधि में ही स्थानीय युवाओं के लिए 8200 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। इन इकाइयों ने 2017-18 से 32.35 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी जारी की है।

सीमेंट ब्लॉकों के विनिर्माण से लेकर लोहे और स्टील की वस्तुओं के विनिर्माण, ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशॉप, टेलरिंग इकाइयां, लकड़ी की फर्नीचर निर्माण इकाइयां, लकड़ी पर नक्काशी की इकाइयां, साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर और सोने के आभूषणों के निर्माण आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें केवीआईसी ने सहायता प्रदान की है। इससे स्थानीय लोगों को सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में मदद मिली है।

यहां तक कि 2020-21 के पहले 6 महीनों के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद केवीआईसी ने विभिन्न क्षेत्रों में कारगिल में 26 और लेह में 24 नई परियोजनाएं स्थापित करने में मदद की, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में 350 नौकरियों का सृजन हुआ।

उल्लेखनीय है कि केवीआईसी पीएमईजीपी योजना के लिए एक नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। 2017-18 से 2020-21 (30 सितंबर तक), केवीआईसी ने कारगिल में 802 परियोजनाएं और लेह में 191 परियोजनाएं स्थापित की हैं। जिसमें कारगिल में 6,781 और लेह में 1421 रोजगारों का सृजन हुआ। केवीआईसी ने कारगिल में इन परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी के रूप में 26.67 करोड़ रुपये का वितरण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान लेह क्षेत्र में 5.68 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।

केवीआईसी के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कारगिल और लेह में रोजगार में हुई वृद्धि में पर्यावरण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण लेह-लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री के नजरिए का योगदान है। इस क्षेत्र में

कारगिल के बारू में एक महिला उद्यमी हमीदा बानो ने सिलाई गतिविधि संचालित की और अपनी यूनिट में 3 अन्य महिलाओं को रोजगार दिया। हमीदा का सालाना कारोबार 12 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

साल में केवल छह महीने तक ही संपर्क स्थापित हो पाता है। कारगिल और लेह ने विभिन्न विनिर्माण गतिविधियों को बनाए रखने की अपार क्षमता दिखाई है। लेह और कारगिल देश के बाकी हिस्सों से लगभग छह महीने तक कटा रहता है। हालांकि, ये इकाइयां इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष सामानों की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

कारगिल और लेह के लाभार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपनी उत्पादन इकाइयां शुरू करने के बाद नौकरियों की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इन इकाइयों ने न केवल उनके लिए स्व-रोजगार सृजित किए हैं बल्कि इस क्षेत्र के कई अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

कारगिल के गांव मिंजी के निवासी मोहम्मद बाकिर ने 10 लाख रुपये के शुरुआती ऋण के साथ सीमेंट ब्लॉक ईंटों की उत्पादन इकाई शुरू की थी। अब उसका 52 लाख रुपये का सालाना कारोबार है। उसने अपनी विनिर्माण इकाई में 8 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। इसी तरह लोहे और इस्पात की वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े इस्माइल नसीरी ने कारगिल के ग्राम पोयेन में 25 लाख रुपये की लागत से अपनी इकाई शुरू की और 10 लोगों को रोजगार दिया है तथा उसकी इकाई 76 लाख रुपये का कारोबार कर रही है।

रोजगार की होड़ ने स्थानीय महिलाओं को भी स्व-रोजगार के लिए प्रेरित किया है जो घर बाहर जाने और स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छुक नहीं थी। केवीआईसी की सहायता से अनेक महिला उद्यमी इन जिलों में कटिंग, सिलाई इकाइयां और ब्यूटी पार्लर सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं।

कारगिल के बारू में एक महिला उद्यमी हमीदा बानो ने सिलाई की गतिविधि में भाग लिया और अपनी यूनिट में 3 अन्य महिलाओं को रोजगार दिया। हमीदा का सालाना कारोबार भी 12 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि लेह-लद्दाख क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद से इस क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

क्र. सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	वितरित की गई मार्जिन मनी (रुपये लाख में)	रोजगार सृजन
01	2017-18	172	0417.12	1099
02	2018-19	462	1491.63	4252
03	2019-20	309	1122.94	2501
04	2020-20 (upto 30.09.2020)	050	0204.00	0350
05	Total	993	3235.69	8202

अरुणाचल प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चे खादी के मास्क पहनेंगे

अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने स्कूल जाते समय हजारों स्कूली बच्चे तिरंगे वाले खादी के फेस मास्क पहनेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्कूली बच्चों के लिए 60,000 उच्च गुणवत्ता वाले खादी कॉटन फेस मास्क की आपूर्ति की है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है।

यह खरीद आदेश बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में अपने छात्रों के लिए खादी फेस मास्क की खरीद की है। खरीद आदेश तीन नवंबर को जारी किया गया था और केवीआईसी ने केवल 6 दिनों में सरकार को तत्काल आवश्यक मास्क की आपूर्ति की है। मास्क का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, केवीआईसी ने विमान से खेप भेजी है।

केवीआईसी ने मास्क में उपयुक्त जगह पर अपने लोगो के साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार को डबल लेयर्ड, तिरंगा वाला कॉटन का फेस मास्क मुहैया कराया है। तिरंगे में बनाए गए फेस मॉस्क का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाना है

केवीआईसी ने इन मास्क के निर्माण के लिए विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया है क्योंकि यह अंदर में 70 प्रतिशत नमी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें हवा भी आसानी से जा सकती है। इसलिए, ये मास्क त्वचा के अनुकूल और लंबी अवधि के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। खादी कॉटन फेस मास्क धोने योग्य, फिर से उपयोग और बायोडिग्रेडेबल हैं।

राज्य सरकार ने जारी आदेश में कहा, "अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 16 नवंबर 2020 से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है और केवीआईसी से 60,000

खादी कॉटन फेस मास्क खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है।"

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को फेस मास्क की आपूर्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह उन छात्रों के लिए था जो 16 नवंबर से कक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा "केवीआईसी के लिए यह सम्मान देने वाला आदेश है और इस तरह के बड़े आदेश से खादी कारीगरों को अतिरिक्त नौकरी मिली है। हमने फेस मास्क के उच्चतम गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करते हुए केवल 6 दिनों में ऑर्डर की आपूर्ति की है।

गौरतलब है कि केवीआईसी ने इस साल अप्रैल में लॉन्च के बाद से 6 महीनों में 23 लाख फेस मास्क बेचे हैं। फेस मास्क के आरामदायक और उच्च गुणवत्ता के कारण केवी आईसी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 12.30 लाख फेस मास्क सहित कई थोक ऑर्डर मिले हैं। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा आम जनता ने भी बार-बार यहां आर्डर दिए हैं।

●●

केवीआईसी का ई-पोर्टल कुम्हारों के लिए समय से पहले दिवाली लाया

(पृष्ठ 7 से आगे.....)

अधिक दीये भी बेचे गए हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मिट्टी की वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री वास्तविक अर्थों में केवीआईसी से जुड़े कुम्हारों का सशक्तिकरण है। श्री सक्सेना ने कहा, 'पहले एक विशेष क्षेत्र के कुम्हार केवल स्थानीय रूप से अपनी वस्तुओं को बेचते थे, लेकिन भारत के खादी के ई-पोर्टल तक पहुंच के साथ, ये उत्पाद देश के हर हिस्से में बेचे जा रहे थे। केवीआईसी ई-पोर्टल के माध्यम से, राजस्थान में निर्मित दीये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, असम, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरस्थ राज्यों में खरीदे जा रहे हैं। इसने उत्पादन में वृद्धि और कुम्हारों की उच्च आय को प्रेरित किया है।' श्री सक्सेना ने कहा, 'कुम्हारों को सशक्त बनाना और मिट्टी के बर्तनों को पुनर्जीवित करना प्रधानमंत्री का सपना है।'

पोखरण में पीएमईजीपी इकाई के ऐसे ही एक कुम्हार मदन लाल प्रजापति ने कहा कि यह पहली बार है जब वह अपने गांव के बाहर दीये बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली में हमारी बिक्री में तेजी आई है। हम दिल्ली में खादी भवन में अपने दीये की आपूर्ति कर रहे हैं और वहां से इसे पूरे देश में ऑनलाइन बेचा जा रहा है। यह मुझे अच्छी आय दिला रहा है।

यह बात उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने इन कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत बिजली के चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए हैं, जिससे उनके उत्पादन और आय में 5 गुना तक वृद्धि हुई है। केवीआईसी ने अब तक कुम्हार समुदाय के 80,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाले 18,000 से अधिक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स वितरित किए हैं।

●●●

वाराणसी में आयोग द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की तरफ से वाराणसी में आयोजित खास खादी प्रदर्शनी में उच्च कोटि के खादी उत्पाद लाए गए जिनमें कश्मीरी शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधान खास चर्चा में थे। इस प्रदर्शनी का उदघाटन 22 नवम्बर, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया।

कश्मीरी शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधान आकर्षण का केन्द्र बने

उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पंजाब से आए सैंकड़ों हस्तकला के कारीगरों ने 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कोविड-19 महामारी के बाद ऐसी दूसरी प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी 15 दिनों (नवंबर 22- दिसंबर 7) तक आयोजित की गयी। इसी साल अक्तूबर में लखनऊ में लॉकडाउन के बाद पहली खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी।

इस प्रदर्शनी में कई खादी संस्थाओं और जम्मू-कश्मीर की अनके 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत काम कर रही इकाइयों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लाया गया शहद, ऊनी कपड़ों और शॉल ने हर किसी का ध्यान खींचा। वाराणसी में इस तरह के शहद की उपलब्धता काफी कम है। इसके अलावा उत्तराखंड से आए उत्पादों की ओर भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसकी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के कारण यह शहद देश भर में काफी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री ने भी मधुमक्खी पालकों से उच्च ऊंचाई वाले शहद के उत्पादन को बढ़ाने की अपील की है जिसकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है।

केवीआईसी ने कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हजारों मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं, जो स्थानीय युवाओं ने केंद्र शासित प्रदेश में शहद उत्पादन में वृद्धि की है।

पश्चिम बंगाल से मलमल के कपड़े, जम्मू-कश्मीर से पश्मीना शॉल और ऊन, पंजाब से कोटि शॉल, कानपुर से चमड़े के उत्पाद, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन और राजस्थान से अचार, मुरब्बा और हर्बल दवा जैसे कई बेहतरीन उत्पाद यहां आए हैं।

बिहार और पंजाब से विभिन्न प्रकार के सिल्क और सूती कपड़े और रेडीमेड कपड़े भी प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान खादी फैब्रिक और रेडीमेड कपड़ों पर 30% की विशेष छूट दी जा रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर आकर्षित करने वाली है जिसने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कठिन समय के दौरान चरखे को बनाए रखा।

उन्होंने कहा, "यह प्रदर्शनी एक अनूठा मंच है जहां वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लोग जम्मू- कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के हस्तनिर्मित खादी उत्पादों को खरीद सकते हैं। 'स्थानीय पहल के लिए मुखर' होना और खादी को बढ़ावा देना एक बड़ा बढ़ावा होगा।"

वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इस शहर ने खादी को बढ़ावा देने और कारीगरों का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्तमान में वाराणसी में 134 खादी संस्थान काम कर रहे हैं, जहाँ कुल कार्यबल का लगभग 80% हिस्सा महिलाओं का है। ●●

केवीआईसी की वर्कशेड योजना के तहत पक्के घर मिलने से पूर्वोत्तर के खादी कारीगरों के चेहरों पर मुस्कान

सुश्री नीरू कलिता से मिलिए, जो असम में नलबाड़ी जिले में एक 44 वर्षीय खादी कारीगर हैं। वह अपने परिवार के साथ, ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से हुए मिट्टी-कटाव के कारण बेघर होने की कगार पर पहुंच गई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग उसकी मदद के लिए आगे आया और कारीगर वर्कशेड योजना के तहत आयोग ने उन्हें घर देने का फैसला किया।

सुश्री कलिता, पिछले 15 वर्षों से खादी स्पिनर के रूप में काम कर रही हैं। इस दौरान उन्हें अपने तीन बच्चों के साथ 14 बार घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनका अस्थायी आवास हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में डूब जाता था। व्यथित परिवार के लिए जीवन अनिश्चित हो गया था। (नदी खोहोनिया के पीड़ित, असम की स्थानीय बोली में उल्लेख किया जाता है) सुश्री कलिता को नलबाड़ी जिले के तापाबोरी गांव में आश्रय मिला। इसी गाँव में केवीआईसी, परिवार के बचाव में आया और उसे एक पक्का घर दिया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कारीगरों के लिए आजीविका सृजन के अलावा, आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे एक बेहतर स्थिति में काम करें जो अंततः उनकी उत्पादकता में सुधार करेगा। श्री सक्सेना ने कहा, "इस पहल को खादी के प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत, "ग्रामीण पुनरुत्थान" के साथ जोड़ा गया है, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण - सबका साथ, सबका विकास के अनुरूप है।

सुश्री कलिता के परिवार में पाँच सदस्य हैं, जो खादी कताई से और ज़मीन के एक छोटे से हिस्से पर खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

हाल के वर्षों में लगातार मिट्टी-क्षरण के कारण, उनकी कृषि भूमि अब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में चली गयी है और इस तरह खादी कताई ही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत रह गया है।

सुश्री कलिता ने घर प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

(शेष पृष्ठ 16 पर...)

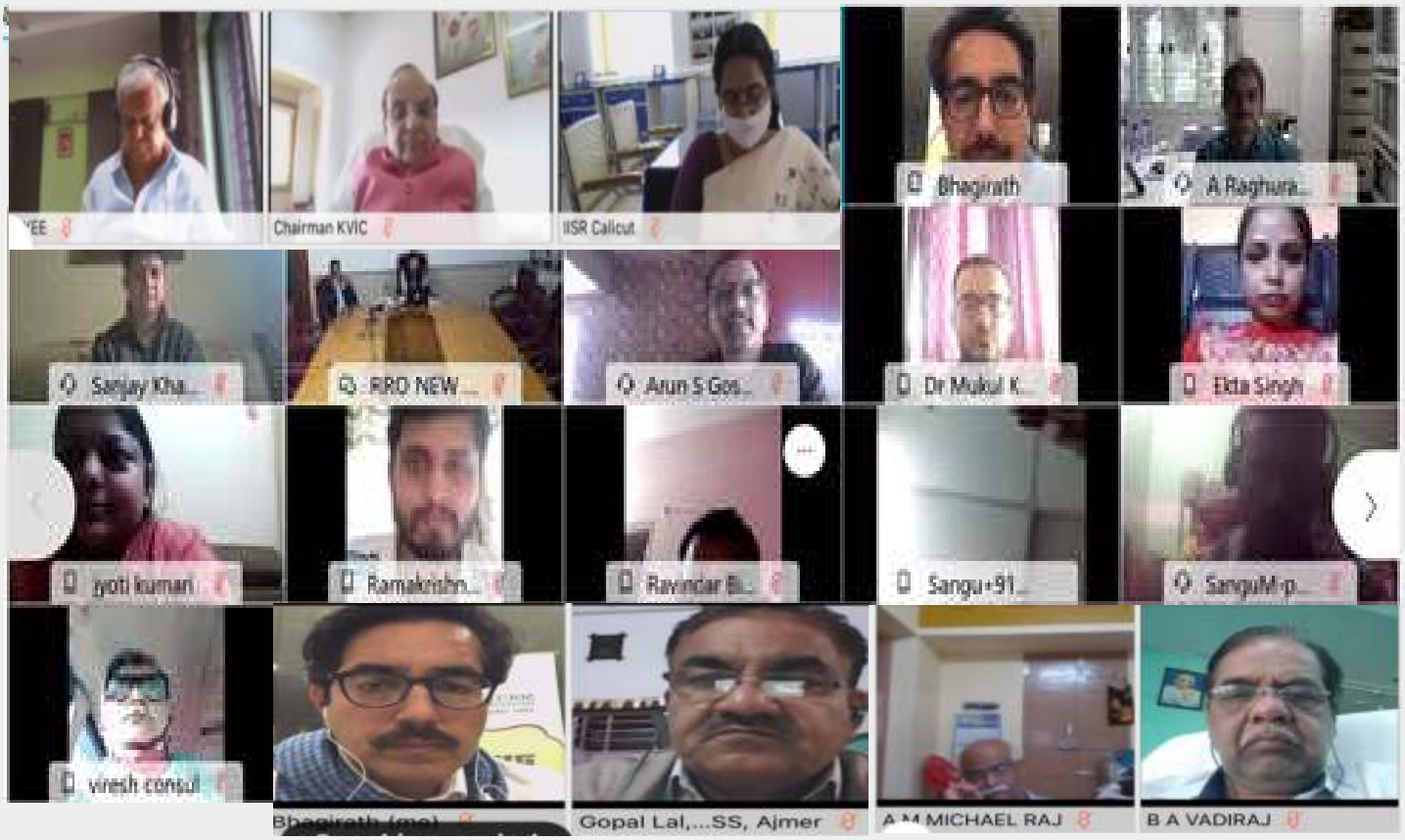

'भारत में मसाला क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर' प्रदान करने के लिए उद्यमियों हेतु वेबिनार में आयोग के अध्यक्ष ने संबोधित किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय स्तर के मसाला वेबिनार "भारत में मसालों में उद्यमिता के अवसर" के दौरान उद्यमियों से प्रतिरक्षा (रोगप्रतिरोधक शक्ति) बढ़ाने वाले मसालों का लाभ उठाने के लिए और भारत को गतिमान बनाने का आह्वान किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के मसाला बोर्ड, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा संयुक्त रूप में 27 नवंबर, 2020 को वेबिनार का आयोजन किया गया। लगभग 100 नवोदित उद्यमी, स्टार्ट अप, प्रगतिशील किसान और आईसीएआर-एनआरसीएसएस और आईसीएआर-आईआईएसआर से वैज्ञानिक, मसाला बिरादरी के सदस्य इस वेबिनार में शामिल हुए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उत्तर क्षेत्र), श्री सत्यनारायण ने भारत के युवाओं को केवीआईसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे मे अवगत कराया, जो मसालों के क्षेत्र में भावी उद्यमी बनना चाहते हैं।

स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के निदेशक (विपणन) श्री

पीएम सुरेश कुमार और डॉ. श्रीशैल केके ने उद्यमियों के लिए मसालों पर योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की, जबकि आईसीए आरएनआरसीएसएस के निदेशक डॉ. गोपाल लाल और आईसीएआर-आईआईएसआर के डॉ. ई जयश्री ने सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी और मसालों के मूल्य वर्धित उत्पादों को शामिल किया । आईसीएआर संस्थानों द्वारा इन उत्पादों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसे उद्यमियों द्वारा व्यवसायिक रूप में लिया जा सकता है।

दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के डॉ. सीडी मेई और डॉ. भागीरथ चौधरी ने उद्यमियों और व्यवसायों को मसालों के गुणवत्ता उत्पादन को मजबूत करने, आईपीएम आधारित उत्पादन में सुधार करने में मदद करने और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के लिए डीबीटी के बायोटेक किसान हब के हिस्से के रूप में उत्पादकों, प्रोसेसरों (संसाधित्रों) और उपभोक्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया।

एफएसएसएआई के डॉ. विजय पाल सिंह ने मसाला उत्पादों के पंजीकरण और सर्टिफिकेट पर एक व्यापक रूप में प्रस्तुतिकरण किया और बेहतर पंजीकरण प्रणाली एफओएससीओ के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया।

एमडीटीसी-केवीआईसी की प्रधानाचार्य सुश्री सरिता, ने वेबिनार का समन्वय करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करने तथा रोजगार व स्वरोजगार का सृजन करने पर जोर दिया।

●●

केवीआईसी की वर्कशेड योजना के तहत पक्के घर मिलने से पूर्वोत्तर के खादी कारीगरों के चेहरों पर मुस्कान

(पृष्ठ 14 से आगे.....)

उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब मैं एक पक्के घर में रह रही हूं। नदी की बाढ़ के कारण हर साल हमें नए स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन सरकारी अधिकारियों से कभी कोई सहायता नहीं मिली। केवीआईसी द्वारा दिए गए इस घर ने मेरे परिवार की सभी चिंताओं को खत्म कर दिया है। अब मैं बेहतर स्थिति में काम कर सकती हूं और मेरे बच्चे सुरक्षित आवास में रह सकते हैं।"

उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 411 खादी कारीगर परिवारों को मकान प्रदान किए हैं। कारीगर वर्कशेड योजना के तहत, केवीआईसी और संबंधित खादी संस्थानों की वित्तीय सहायता से कारीगरों को किफायती पक्का घर प्रदान किया जाता है।

66,000 रुपये की लागत वाले इन घरों का डिजाईन आईआईटी, गुवाहाटी के परामर्श से तैयार किया गया है।

केवीआईसी द्वारा 60,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं तथा शेष 6000 रुपये का योगदान उन खादी संस्थानों द्वारा किया जाता है, जिनमें कारीगर पंजीकृत होते हैं।

●●

आयोग के केन्द्रीय पूनी संयंत्र, सीहोर ने 27 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया । इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए गये।

आयोग के अध्यक्ष ने अहमदाबाद में पश्चिम क्षेत्र खादी मार्क समिति एवं अन्य खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों की समीक्षा की |

केवीआईसी के हनी मिशन से प्रवासी श्रमिकों को पहली आय अर्जित

आगामी महीनों में अधिक उत्पादन की उम्मीद

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कोविड-1 9 महामारी को देखते हुए उठाए गए स्व-निरंतरता उपायों के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। विपदा में फंसे प्रवासी श्रमिक अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश में केवीआईसी के शहद मिशन में शामिल हुए। श्रमिकों ने पहले शहद उत्पादन का लाभ उठाया है। आशा है दिसम्बर से मार्च महीने में उत्पादन बढ़ेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पांच प्रवासी श्रमिकों ने मधुमक्खियों के 50 बॉक्स से 253 किलोग्राम शहद निकाला। ये बॉक्स इसी वर्ष 25 अगस्त को उन्हें दिए गए थे। अपरिकृत शहद 200 रुपये प्रति किलो के औसत से बिकता है और इस दर से प्रवासी श्रमिकों को लगभग 50 हजार रुपये प्राप्त होने की आशा है।

इसका अर्थ प्रत्येक लाभार्थियों की 10 हजार रुपये की औसत आय है। इस क्षेत्र में केवीआईसी के प्रशिक्षण के बाद 70 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खियों के 700 बक्से दिए गए थे। मधुमक्खी के शेष बक्सों में से आने वालों दिनों में शहद निकाला जाएगा।

दिसम्बर से मार्च महीने में मधुमक्खियों के इन बक्सों से कम से कम 5 गुना शहद प्राप्त होगा क्योंकि सीजन के दौरान यूकेलिप्टस और सरसो की फसल अपने चरम पर होगा। इनमें से प्रत्येक बक्सों से पीक सीजन में 25 किलोग्राम शहद निकलेगा।

मधुमक्खी पालक अपने बक्सों को हरियाणा, राजस्थान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजने में सक्षम होंगे। इन क्षेत्रों में

मधुमक्खियों को पर्याप्त पराग तथा नेक्टर मिलेंगे। इनका इस्तेमाल शहद उत्पादन में होगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा के प्रवासी श्रमिकों को अपनी जड़ों से जुड़ने और स्व-रोजगार प्राप्त करते देख प्रसन्नता हो रही है।

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शहद मिशन के साथ अन्य शहरों से अपने घर चले गए श्रमिकों को इस काम में लगाया गया।

श्रमिक महज तीन महीनों में अपने बलबूते आजीविका कमा रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि आने वालें महीनों में शहद का उत्पादन और श्रमिकों की आय कई गुना बढ़ेगी।

लाभार्थियों ने समर्थन के लिए केवीआईसी को धन्यवाद दिया और कहा कि आयोग ने हमें मधुमक्खी पालन से काम की तलाश में अन्य शहरों में गए बिना अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया।

सहारनपुर जिला में केवीआईसी के मधुमक्खी पालक अमित कुमार ने कहा 'मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके विजन से हमारे लिए स्थानीय रोजगार सृजन हुआ है। हम पांच श्रमिकों को तीन महीनों में ही 50 मधुमक्खी के बक्से मिले। इनमें से 253 किलोग्राम शहद निकाला गया।'

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को देखते हुए केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को शहद मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण योजना और डिग्निटी परियोजनाओं में शामिल किया।

उन्हें आवश्यक उपकरण वितरित किए जाने के अतिरिक्त केवीआईसी ने नए मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया।

●●

आयोग ने संविधान दिवस मनाया

लोगों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 26 नवंबर 2020 को केवीआईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस मनाया।

आयोग मुख्यालय में आयोग की मुख्य सर्तकता अधिकारी डॉ. संघमित्रा द्वारा संविधान प्रस्तावना सामूहिक तौर पर पढ़ी गयी।

मदुरै

रा.का.महाराष्ट्र

रायपुर

के.पू.स. त्रिचूर

भोपाल

बोरीवली

देहरादून

चेतावनी सूचना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) ने सोशल मीडिया पर काउंटर चेक जानकारी के लिए स्थापित PIBFACTCHECK के माध्यम से यह पहचान की है कि कुछ फर्जी लोग / बेईमान एजेंसियां / व्यक्ति अर्थात् नई दिल्ली के श्री अखिल वर्मा और श्री रोहित सिंह, मुख्य रूप से अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के बहाने धोखाधड़ी कर रहे हैं। वे गैर-कानूनी रूप से भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह, केवीआईसी के लोगो और खादी और ग्रामोद्योग आयोग और उसके कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइटों के अन्य विवरणों का उपयोग कर रहे हैं।

यह भी देखा गया है कि उक्त दल योजना के बहाने भावी उद्यमियों को धन इकट्ठा करने के लिए भ्रमित कर रहे हैं।

सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर चेतावनी दी गई है कि उपरोक्त धोखेबाज व्यक्ति अनधिकृत हैं और उनके पास केवीआईसी और न ही एमएसएमई मंत्रालय के साथ कोई अनुमोदन / मान्यता / संबद्धता नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी), आम तौर पर सार्वजनिक रूप से इस तरह की धोखाधड़ी वाली प्रथाओं के खिलाफ सचेत रहने और इस तरह की भ्रामक प्रथाओं के शिकार होने से बचने का आग्रह करता है।

यह भी आम जनता के ध्यान में लाया जाता है कि केवीआईसी ने किसी भी निजी पार्टी / एजेंसी / बिचौलिए या फ्रैंचाइजी आदि को पीएमईजीपी परियोजनाओं के प्रचार या मंजूरी या पीएमईजीपी कार्यक्रम के तहत कोई वित्तीय सहायता या किसी भी संभावित उद्यमी / लाभार्थियों से नहीं जोड़ा है जो इस तरह की एजेंसी से काम कर रहे हों, वे अपने जोखिम और परिणामों के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगे।

श्री ए.एल.मीणा, राज्य निदेशक, महाराष्ट्र ने सिंधुदुर्ग जिले के फोंडाघाट गाँव में कुम्हारी उद्योग पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया, और 28 और 30 नवंबर, 2020 को क्रमशः महाराष्ट्र के कुदाल में पीएमईजीपी के तहत पेट बोतल निर्माण इकाई और काजू प्रसंस्करण इकाई तथा सिंधुदुर्ग जिले में बांस स्फूर्ति क्लस्टर का भी निरीक्षण किया।

29 नवंबर, 2020 को उन्होंने सिंधुदुर्ग में सावंतवाड़ी में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद कुशल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ 60 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स और 6 ब्लॉन्जर मशीनों का वितरण किया।

महाराष्ट्र में पीएमईजीपी इकाईयों एवं बांस स्फूर्ति क्लस्टर का निरीक्षण

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

4 Sunday, 22 November 2020

Khadi registers record sale

Single day sale at flagship CP outlet crossed Rs 1 cr for 4 times in 40 Days

By Chandrashekhar Hendve

Overcoming the economic distress and the fear surrounding Corona pandemic, this festive season has yielded great dividends to the Khadi artisans with a record sale of Khadi products. In just 40 days since October 2 this year, Khadi's single-day sales figure has crossed Rs 1 crore mark for 4 times at the flagship Khadi India outlet at Connaught Place in New Delhi.

On November 13, the total sale at this outlet stood at Rs 1.11 crore, the highest single-day sale figure recorded this year. Ever since the business activities resumed after the lockdown, Khadi sales figure touched Rs 1.02 crore mark on Gandhi Jayanti (October 2) this year followed by Rs 1.05 crore sales on October 24 and Rs 1.06 crore on November 7.

Earlier in 2018, the single-day sale had also crossed the Rs 1 crore mark on 4 occasions with the highest single-day sale for the year touching Rs 1.25 crore on October 13. Khadi's highest ever single-day sale was recorded at Rs 1.27 crore on October 2, 2019. Notably, before 2016 Khadi's single day sale had never crossed the Rs 1 crore mark. On October 22, 2016, the single day sale at Khadi India outlet in CP had reached Rs 116.13 crore.

KVIC Chairman Shri Vinai Kumar Saxena attributed the massive sale figures to the frequent appeals of the Hon'ble Prime Minister to promote "Swadeshi", particularly Khadi. "It is heartening to see a large number of Khadi lovers coming out to support artisans who form the backbone of the Khadi and Village Industries sectors. Despite the pandemic, Khadi artisans kept the production activities going in full vigor and the fellow countrymen have reciprocated with the same zeal," Saxena said, adding despite the economic slowdown, KVIC has managed to maintain the pace of Khadi's growth.

The tremendous sale of Khadi products this year assumes greater significance. While almost all activities were suspended during the Covid-19 lockdown, KVIC continued with its diverse activities across the country that includes the manufacturing of face masks and personal hygiene products like hand wash and hand sanitizers apart from a vast range of fabric and village industries products.

The lockdown had a severe bearing on the livelihood of Khadi artisans but the Hon'ble Prime Minister's appeal for "Aatmanirbhar Bharat" and "Vocal for Local" infused a new life into the local manufacturing particularly the Khadi and Village Industries sectors.

Khadi's Single Day Sale Figure

- October 4, 2014 – Rs 66.81 lakh
- October 2, 2015 – Rs 91.42 lakh
- October 22, 2016 – Rs 116.13 lakh
- October 17, 2017 – Rs 117.08 lakh
- October 2, 2018 – Rs 105.94 lakh
- October 13, 2018 – Rs 125.25 lakh
- October 17, 2018 – Rs 102.72 lakh
- October 20, 2018 – Rs 102.14 lakh
- October 2, 2019 – Rs 127.57 lakh
- October 2, 2020 – Rs 102.24 lakh
- October 24, 2020 – Rs 105.62 lakh
- November 7, 2020 – Rs 106.18 lakh
- November 13, 2020 – Rs 111.40 lakh

दैनिक बहुरंगी वार्ता

कुंभार कारागीरांना इलेक्ट्रिकल चाकांचे वाटप

प्रतिनिधी, नांदेड

नांदेड जिल्ह्यातील कुंभार काम करणाऱ्या कारागिरांना इलेक्ट्रिकल चाकांचा दहा दिवस प्रशिक्षण देऊन कारागीरांना इलेक्ट्रिकल चाकांचे लहान ता.अर्धापूर येथे वाटप करण्यात आले.

पूर्वी मातीच्या चाकावर काम करताना काठीच्या साह्याने प्रचंड मेहनत घेऊन कुंभार कारागिर मातीची भांडी बनवत होते. परंतु बदलत्या काळात आधुनिक यंत्राच्या साह्याने इलेक्ट्रिकल चाकावर काम केल्यास कमी मेहनतीत व सुखित राहून खूप मोठ्या प्रमाणात मातीची वेगवेगळी भांडी बनवण्यास मदत होणार आहे. सदर इलेक्ट्रिकल चाके खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेच्या पाठपुराव्याने मिळाली असून त्यासाठी १० दिवस प्रशिक्षण

कार्यक्रमासाठी स्वाभिमानी कुंभार समाज सामाजिक संस्थेचे नांदेड जिल्हा अध्यक्ष विजय देवडे यांनी अथक परिश्रम घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी केला.

व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारा नितीनजी गडकरी व खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मुंबई येथील प्रमुख अधिकारी मिना साहेब, राजीव खत्री, शिवाजण साहेब, पी.डी.शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.

नांदेड जिल्ह्यात राहिलेल्या कारागिरांना लवकरच खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल मिळवून देण्याचा संकल्प आमचा असून नांदेड जिल्ह्यात कलस्टरचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय माती कला सेलचे चेअरमन श्री दत्ता कुंभार डाळसकर साहेब यांनी विजयराव देवडे यांना दिल्या. त्यासाठी सर्वतोपरी मदत अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेच्या वतीने करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मोहनराव जाधळे, प्रदेश अध्यक्ष श्याम शेठ राजे, राष्ट्रीय माती कला सेलचे चेअरमन दत्ता कुंभार डाळसकर, विश्वनाथराव कोलमकर, विजयराव देवडे, त्र्यंबकराव गोरगीळे, नंदकुमार सांगपुरे, नकुलेश कुंभार, श्रीराम हेलंग, बाळासाहेब कुंभार, शिवाजीराव पांगरेकर, बालाजी धुमलवाड, शंकरराव नांदेडकर, बालाजी जोल्हे, लक्ष्मण बिभुते, उमेश पाडे, बालाजी टीमकेकर, डी.आय. मरकंटे, शिवाजी टीमकीकर, संदीप अन्नुरे, ज्ञानेश्वर देवडे, गिरीश चिचकुंडे, गणेश येवार, मारोती बलुरकरसह इतर पदाधिकारी व खूप मोठ्या प्रमाणात समाज बांधव उपस्थित होते.

Scanned with CamScanner

Chairman KVIC @ChairmanK... · 8h

Khadi India stands out as the Ekta Mall inaugurated by Hon'ble Prime Minister in Gujarat's Kevadia. PM's push has revolutionised Khadi & village industries as the most loved Indian Brand & a Tool of Self-Sustainable employment @PMOIndia @nitin_gadkari @BJP4India @sambitswaraj

1 7 25

Ministry of MSME @minms... · 8h

चाँद-सितारे सिर्फ आसमान में नहीं, भारत में बने कपड़ों पर भी दिखते हैं। अपने कारीगरों और बुनकरों के हाथों का कमाल देखिये ! Bring them home this diwali and be "उजाले इन उमीदों के".
#msmechampions @PIB_India

*This content is licensed for personal use only, not for any commercial use.

राजस्थान

सौगात • केंद्रीय रेल मंत्री ने अलवर के दिगावड़ा स्टेशन पर विद्युतीकृत दिगावड़ा-बांदीकुई रेलवे ट्रैक का किया उद्घाटन

राजस्थान में 7 नई रेल लाइन डालने का काम जारी, देश के सभी स्टेशनों पर कुल्हड़ में ही मिलेगी चाय : गोयल

हर साल 240 किमी रेल ट्रैक का विद्युतीकरण

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

फेसबुक पर

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

इंस्ट्राग्राम पर

• Special Day posts •

पर्यावरणानुकुल मनमोहक खादी डिजाइनर परिधान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

Khadi India

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"